सिंडिकेट बैंक

बनाम

श्री प्रभा डी. नाइक और अन्य

26 मार्च, 2001

(बी. एन. किरपाल, यू. सी. बनर्जी और बृजेश कुमार, जे. जे.)

सीमा अधिनियम, 1963-धारा 24 (2)-पुर्तगाली नागरिक संहिता-अनुच्छेद 535-गोवा में बैंक द्वारा दिए गए ऋण के पुनर्भुगतान में चूक-वसूली के लिए मुकदमा-सीमा का कानून-सीमा अधिनियम के तहत सीमा द्वारा वर्जित मुकदमे को खारिज करना-सीमा के लिए पुर्तगाली नागरिक संहिता का आवेदन-आयोजित, नागरिक संहिता का सीमा के संबंध में कोई आवेदन नहीं है क्योंकि इसे दो केंद्रीय अधिनियमों, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 द्वारा निहित रूप से निरस्त किया गया है-सीमा अधिनियम सही ढंग से लागू किया गया है-गोवा, दमन और दीव प्रशासन, 1962-धारा 5।

क़ानूनों की व्याख्याः

निहित निरसन का सिद्धांत-आयोजित, सिद्धांत तब लागू होता है जब विशेष विधान के माध्यम से कोई स्पष्ट निरसन नहीं होता है।

प्रतिमुकदमा गोवा में अपीलार्थी-बैंक द्वारा दिए गए ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करता है। बैंक ने निचली अदालत के समक्ष भविष्य के ब्याज के साथ राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। मुकदमा को निचली अदालत ने सीमा अधिनियम, 1963 के तहत सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने भी इस आधार पर याचिका खारिज कर दी। इसलिए याचिका दायर की गई है।

अपीलार्थी-बैंक ने तर्क दिया कि सीमा का कानून जो गोवा में लागू होता है वह पुर्तगाली नागरिक संहिता है न कि सीमा अधिनियम, 1963; कि संहिता जारी है क्योंकि इसे गोवा, दमन और दीव प्रशासन, 1962 की खंड 5 द्वारा आवश्यक एक विशिष्ट कानून द्वारा निरस्त नहीं किया गया है; कि पुर्तगाली नागरिक संहिता को किसी भी निरसन क़ानून द्वारा पूर्व-स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया गया है; कि सीमा अधिनियम, 1963 स्पष्ट रूप से सीमा अधिनियम, 1908 को निरस्त करता है न कि संहिता जैसे स्थानीय कानूनों को; कि गोवा में आम आदमी अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय और अधिकार और देनदारियों को बनाने वाले अन्य व्यक्तिगत दायित्वों के लिए संहिता से मार्गदर्शन लेना जारी रखता है।

प्रतिवादीओं ने तर्क दिया कि सीमा अधिनियम खंड 1 (2) के अनुसार गोवा में लागू होता है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।

न्यायालय याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. पुर्तगाली सिविल कोड के अनुच्छेद 535, जिसमें अनुबंधों को विनियमित करने वाले अध्याय III में सीमा के प्रावधान हैं, को भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अनुबंध अधिनियम के तहत एक ही अध्याय में होने वाले अनुबंधों से संबंधित सीमा के लिए निर्धारित अवधि को अनुबंध के अन्य प्रावधानों के साथ जाने के बजाय एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में जीवित नहीं कहा जा सकता है, जो अनुबंध अधिनियम के अनुकूलन के कारण प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार इसे एक निहित निरसन कहा जाता है। जहाँ तक अध्याय का संबंध है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुकूलन के तथ्य के कारण एक स्पष्ट निरसन की आवश्यकता कभी महसूस नहीं की गई थी। या तो अध्याय अपनी संपूर्णता में जीवित रहता है या यह

अपने सभी क्षेत्रों में नष्ट हो जाता है-यह अनुबंध से संबंधित एक अध्याय है और इसके प्रवर्तन की अवधि निर्धारित करता है। कोई विच्छेदन संभव नहीं है। [723-बी-डी]

1.2.मुकदमा की वाद हेतुक अर्थात समझौते के संदर्भ में उधार दिया गया धन और अग्रिम धन, वचन पत्र के स्वीकृत निष्पादन के कारण वचन पत्र अधिनियम के साथ पठित अनुबंध अधिनियम द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होता है और इस तरह से संहिता द्वारा शासित नहीं कहा जा सकता है। यदि कार्यवाही शुरू करने का अधिकार संहिता के दायरे से बाहर चला जाता है, तो बाद वाला इसकी प्रवर्तनीयता को नियंत्रित नहीं कर सकता है। सिविल संहिता अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। राज्य के कानून, दोनों कानूनों के अनुरूप अधिसूचना जारी करने से पहले इसकी प्रयोज्यता किसी भी तरह से प्रतिबंधात्मक नहीं थी। पुर्तगाली सिविल कोड को सीमा का अधिनियम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से मौजूदा कार्रवाई के अधिकारों के प्रवर्तन को रोकने के लिए अपने संचालन का विस्तार नहीं कर सकता है। सिविल संहिता को राज्य में व्यापक कानून का एक संकलन नहीं माना जा सकता है जो स्थिति की आवश्यकता को पूरा करता है और साथ ही इसे समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट अवधि प्रदान करता है। या तो संहिता पूरी तरह से लागू होती है या नहीं-इसके बारे में कोई आधा रास्ता नहीं है। [724-एफ-एच; 725-ए-बी]

2.1.भारतीय कानून के तहत अधिकार के अस्तित्व के कारण, अर्थात। समझौता अधिनियम और परक्राम्य लिखत अधिनियम, पुर्तगाली कानून के तहत उपचार के विलुप्त होने को निहित रूप से निरस्त नहीं माना जा सकता है। निहित निरसन के सिद्धांत को विचाराधीन मामले के तथ्यों में अपनी जगह लेनी होगी। निहित अर्थहीनता के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जहां किसी विशेष प्रावधान को बनाए रखने का इरादा नहीं किया जा सकता था और यदि इसे बनाए रखा जाता है, तो परिणामी प्रभाव एक बेतुका होगा। न्यायालय निहितार्थ द्वारा निरसन के आधार पर ऐसा

होने की घोषणा किए बिना नहीं रह सकते। [725-जी-एच; 726-ए]

2.2.यदि केवल सीमा के प्रश्न से संबंधित स्थानीय कानून को प्रचलित रखने का कोई इरादा होता, तो सीमा अधिनियम में खंड 1 (2) के तहत एक स्पष्ट बहिष्करण होता जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए किया गया था और इसकी अभावि में न तो विपरीत इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है और न ही उल्लंघन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किसी भी स्थिति में, पुर्तगाली सिविल कोड को भारतीय अनुबंध अधिनियम या परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली वाद हेतुक लिए सीमा की एक अलग और अलग अवधि प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि सिविल कोड को एक साधन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उससे उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के कारण को केवल उसके तहत नियंत्रित किया जाना चाहिए और अन्यथा नहीं। संपूर्ण नागरिक संहिता को एक स्थानीय कानून या विशेष कानून के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें उस विशेष नागरिक संहिता के तहत उत्पन्न होने वाले अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीमा के प्रश्न से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, न कि उसी के लिए। इस मुद्दे पर एक विरोधाभासी दृष्टिकोण न केवल एक अर्थहीनतापन को जन्म देगा, बल्कि देश के कानून को पूरी तरह से अनुचित बना देगा। [726-जी-एच; 727-ए-बी]

3. 1.1.1964 से अस्तित्व में आने वाले सीमा अधिनियम के तथ्य के मद्देनजर, पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुच्छेद 535 को निहित रूप से निरस्त नहीं कहा जा सकता है। पूरे देश के लिए सीमा का एक सामान्य कानून 1963 का सीमा अधिनियम है, और पुर्तगाली नागरिक संहिता को सीमा अधिनियम की खंड 29 (2) के अर्थ के भीतर सीमा की एक अलग अवधि निर्धारित करने वाले गोवा, दमन और दीव राज्य के लिए लागू एक स्थानीय कानून या विशेष कानून नहीं कहा जा सकता है और किसी भी स्थिति में, 1963 के सीमा अधिनियम के तहत स्थानीय कानून को बचाने का सवाल

पैदा नहीं होता है और न ही हो सकता है। [728-डी-एफ]

जस्टिनियानो ऑगस्टो डी पाइडेड बैरेटो बनाम एंटोनियो विसेंट दा फोंसेका और अन्य, ए. आई. आर. (1979) एस. सी. 984, ने खारिज कर दिया।

सी. बीपथुमा और ओआरएस अन्यवेलासरी शंकरनारायण कदामोलिथया और अन्य, ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 241 और एम/एस. कैडर कंस्ट्रक्शंस बनाम एम/एस. तारा टाइल्स, ए. आई. आर. (1984) बॉम। 258, संदर्भित।

स्पीयर बनाम हार्टली, [1800] 3E.sl 81 170 ER 545 और मैकेन बनाम R. W. मिलर एंड कंपनी। (दक्षिण ऑस्ट्रेलिया) पीटीवाई। लिमिटेड, (174 सी. एल. आर. 1991-92 पृष्ठ 1), संदर्भित।

बी. बी. मित्रा का सीमा अधिनियम (20वां संस्करण); कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम (वॉल्यूम। 72); चेसिस्टियर एंड नॉर्थ, प्राइवेट इंटरनेशनल लिमिटेड 11 वीं संस्करणःमैकलियोडःसंदर्भित कानूनों का टकराव।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल याचिका सं 4944/1989

उच्च न्यायालय बंबई 1985 के एल. पी. ए. सं. 22 के निर्णय और आदेश दिनांकित 8.10.85 से।

के साथ

सिविल याचिका सं. 4945/1989,

अपीलकर्ता के लिए ओ. पी. शर्मा, अभिषेक अत्रे, के. आर. गुप्ता और आर. सी. गुब्रेले।

ध्रुव मेहता, सुश्री शोभा और प्रतिवादीओं के लिए एस.के. मेहता।

न्यायालय का निर्णय बनर्जी, जे. द्वारा दिया गया था।

पुर्तगाली सिविल कोड के अनुच्छेद 535 की व्याख्या के साथ भारतीय सीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता, जिसे गोवा, दमन और दीव राज्य में सीमा का शासी कानून कहा जाता है, इस अपील में विचार के लिए केंद्र बिंदु है। यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि सीमा अधिनियम, 1963 की खंड 29 (2) में सीमा अधिनियम की बचत के प्रावधान हैं जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि खंड 4 से 24 (दोनों सहित) में निहित प्रावधान केवल उस हद तक लागू होंगे जहां तक वे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। खंड 29 (2) के तहत उक्त प्रावधान और खंड 29 (2) के अर्थ के भीतर एक स्थानीय कानून होने के रूप में सीमा के प्रश्न से संबंधित पुर्तगाली नागरिक संहिता की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय जस्टिनियानो ऑगस्टो डी पिडाडे बैरेटो बनाम एंटोनियो विसेंट दा फोंसेका और अन्य के मामले में, ए. आई. आर. (1979) एस. सी. 984 इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुर्तगाली-नागरिक संहिता के प्रावधानों का मुख्य भाग जो मुकदमों आदि की सीमा के विषय से संबंधित है और केवल केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव में लागू है, सीमा अधिनियम, 1963 की खंड 29 (2) के अर्थ के भीतर स्थानीय कानून है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि पुर्तगाली नागरिक संहिता के इन प्रावधानों को सीमा अधिनियम, 1963 में पढ़ा जाना चाहिए, जैसे कि सीमा अधिनियम की अनुसूची में उत्परिवर्तन के साथ संशोधन किया गया है और किसी भी तरह की अस्वीकृति का सवाल नहीं उठता है और न ही उत्पन्न हो सकता है। पहले का निर्णय (जस्टिनियानो (सुप्रा)), स्पष्ट रूप से गोवा, दमन और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और मध्यस्थता संहिता का विस्तार) अधिनियम, 1965 की खंड 3 के प्रावधानों से प्रेरित था, जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और मध्यस्थता अधिनियम, 1940 दोनों को केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव तक विस्तारित किया गया था और इस परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 में कहा गया हैः

"अधिनियम की धारा 4 केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव में लागू कानून के इतने हिस्से को निरस्त करती है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अनुरूप है। यह अधिनियम न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहितार्थ से पुर्तगाली नागरिक संहिता में निहित सीमा से संबंधित प्रावधानों को निरस्त करता है।

हालाँकि, इस मोड़ पर तथ्यात्मक मैट्रिक्स की ओर मुड़ते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि-सिंडिकेट बैंक बॉम्बे में उच्च न्यायालय की पणजी पीठ के आदेश के खिलाफ पहली अपील संख्या 73/1985 में अपील कर रहा है, जिसमें उच्च न्यायालय एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यदि वाद हेतुक, जैसा कि विचाराधीन मामले में है, पुर्तगाली कानून के बाहर उत्पन्न हुआ है, तो सीमा की अवधि से निपटने वाले उपरोक्त कानून का हिस्सा लागू नहीं होगा और यह भारतीय सीमा अधिनियम द्वारा नियंत्रित होगा और चूंकि वाद हेतुक निम्नलिखित होगाः

विचार पुर्तगाली कानून के बाहर उत्पन्न हुआ, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, पणजी के फैसले और डिक्री में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि शिकायत की अस्वीकृति को सीमा द्वारा बाधित किया जा रहा है।

संयोग से, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती का एकमात्र आधार भी सीमा के मुद्दे से संबंधित था। हालाँकि, विद्वान सिविल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने मैसर्स कैडर कंस्ट्रक्शंस बनाम मैसर्स तारा टाइल्स, ए. आई. आर. (1984) बॉम के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया। 258 जिसमें उच्च न्यायालय इसके निर्णय पर विचार करने के बाद। जस्टिनियानो के मामले (ऊपर) में अदालत ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 25 में स्थिति का सारांश नीचे दिया हैः

"25. अब हम इस संबंध में अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

(i) पुर्तगाली नागरिक संहिता या इस केंद्र शासित प्रदेश में सीमा की अवधि से संबंधित अन्य संहिताओं में प्रावधान भारतीय सीमा अधिनियम, 1963 की खंड 29 (2) के अर्थ के भीतर स्थानीय कानून हैं, जैसा कि जस्टिनियानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया गया है।

((ii) लेकिन वे उन संहिताओं के तहत अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विशेष कानून भी हैं जिनका वे स्वयं एक हिस्सा हैं।

(iii) यदि केंद्र शासित प्रदेश में लागू पुर्तगाली कानून के तहत वाद हेतुक कोई कारण उत्पन्न होता है, तो कार्रवाई के उस कारण के आधार पर मुकदमे के मुकदमा सीमा की अवधि प्रासंगिक पुर्तगाली कानून में उल्लिखित अवधि होगी। हालाँकि, यदि पुर्तगाली कानून में प्रासंगिक प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है और वाद हेतुक पहले ही सामने आ गया है

कानून का निरसन तब, निरसन के बावजूद, वाद हेतुक उस कारण के आधार पर एक मुकदमा दायर किया जा सकता है और उस मामले में भी सीमा की अवधि से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान संहिता में ही प्रावधान होगा।

(iv) हालांकि, यदि वाद हेतुक पुर्तगाली कानून के बाहर उत्पन्न हुआ है, तो सीमा की अवधि से संबंधित कानून का वह हिस्सा लागू नहीं होगा; दूसरी ओर, पुर्तगाली कानून के बाहर उत्पन्न होने वाली

कार्रवाई के कारण के आधार पर दायर किया गया मुकदमा भारतीय सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

इन अपीलों की सुनवाई के दौरान, कैडर कंस्ट्रक्शन के मामले (ऊपर) में निर्धारित तर्कों पर भरोसा किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि किसी भी स्थिति में पुर्तगाली सिविल कोड को सीमा के मुद्दे से संबंधित एक विशेष कानून नहीं होने के कारण, संहिता को सीमा अधिनियम की खंड 29 (2) के अर्थ के भीतर एक विशेष कानून या स्थानीय कानून नहीं कहा जा सकता है और मामले की सुनवाई करने वाले इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्थिति के मूल्यांकन पर, प्रस्तुतिकरण को आकर्षक पाया और इस तरह, एक बड़ी पीठ द्वारा जस्टिनियानो के मामले (ऊपर) में निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके साथ ही इस पीठ का गठन गोवा, दमन और दीव राज्य में सीमा अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए किया गया है।

इस मुद्दे पर विचार करने से पहले यह ध्यान दें समीचीन है कि हालांकि पहली बार सीमा कानून की वैधानिक मान्यता 1859 के अधिनियम 14 द्वारा और उसके तहत 1859 में तैयार की गई थी, लेकिन देश में सीमा की अवधि तय करने के लिए समय-समय पर विभिन्न नियम पारित किए गए थे। हालाँकि, बाद में, 1908 के अधिनियम ने 1859 के पहले के अधिनियम से एक बड़ा बदलाव प्रदान किया और फिर से सीमा से संबंधित अधिनियम को सीमा अधिनियम, 1963 के माध्यम से क़ानून की पुस्तक में जगह मिली।

संयोग से, यह ध्यान दिया जा सकता है कि हालांकि पुराने हिंदू कानून ने प्रिस्क्रिप्शन और सीमा दोनों को मान्यता दी थी, लेकिन मुस्लिम न्यायशास्त्र ने उनमें से किसी को भी मान्यता नहीं दी। हालाँकि, 1963 के सीमा अधिनियम के संदर्भ में

सीमा का नया अधिनियम कोई अनुमोदन या वर्ग भेद नहीं करता है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों अधिनियम सीमा के अधिनियम के लिए उत्तरदायी हैं जैसा कि वर्तमान में क़ानून की पुस्तक में मौजूद है (इस संदर्भ में देखें बी. बी. मित्र का सीमा अधिनियमः20 टी. एड.)।

आगे के तथ्यात्मक आधार पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंडिकेट बैंक ने एक करोड़ रुपये की राशि की वसूली के लिए एक विशेष मुकदमा (1985/ए का मुकदमा संख्या 5) दायर किया। 32, प्रतिमुकदमी संख्या 1 (वर्तमान में प्रतिमुकदमी संख्या 1) के खिलाफ प्रधान देनदार के रूप में मुकदमी की बेतिम शाखा, गोवा में उधार और अग्रिम राशि के लिए और प्रतिमुकदमी संख्या 2 (वर्तमान में प्रतिमुकदमी संख्या 2) के खिलाफ उक्त ऋण की वसूली के लिए सह-बाध्यकारी-ग्वार-एंटोर के रूप में भुगतान करने तक <आईडी 2 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज के साथ। ऋण जुलाई, 1978 में उनके व्यवसाय के लिए दिया गया था, जिसे प्रतिवादी ने दिसंबर, 1978 तक भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी, उक्त राशि के लिए एक डिमांड वचन पत्र के निष्पादन पर, एक डीड ऑफ हाइपोथेकेशन के साथ एक वितरण पत्र दोनों दिनांकित 22.7.78। मुकदमा में प्रतिवादी होने के नाते प्रतिवादी मुकदमा े के अनुसार ऋण चुकाने में विफल रहे और मुकदमी की कई मांगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए 17 जनवरी, 1985 को मुकदमा दायर किया गया। अभिलेखों से पता चलता है कि कार्यालय अधीक्षक ने सीमा के आधार पर एक कार्यालय आपत्ति उठाई और अभियोक्ता ने, हालांकि, तर्क दिया कि जस्टिनियानो के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के कारण मुकदमा सीमा से वर्जित नहीं है और इस तरह, मुकदमा केवल सीमा के प्रारंभिक मुद्दे पर सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे को इस आधार पर खारिज करने का आदेश दिया गया था कि उसे सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। अपीलों का भी वही भाग्य था जो यहाँ पहले

देखा गया था और इसलिए अनुमति देने पर इस न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी।

मान लीजिए, देश में पुर्तगाली औपनिवेशिक अधिकारः गोवा, दमन और दीव द्वीप 20 दिसंबर, 1961 से भारत के क्षेत्र का हिस्सा बन गए और संविधान के बारहवें (संशोधन) अधिनियम, 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को उक्त तिथि (20 दिसंबर, 1961) से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इसके निगमन से पहले, मौजूदा पुर्तगाली नागरिक संहिता थी जिसमें सीमा से संबंधित कानूनों सहित कई कानूनों का विवरण था। संभवतः स्थिति का व्यापक आकलन आदेशने के लिए, इस मोड़ पर प्रावधानों पर एक नज़र डालना बेहतर होता, लेकिन इसकी सामग्री के संबंध में तथ्यों की स्वीकृत स्थिति के तथ्य के कारण, कई कानून होने के कारण और चूंकि श्री शर्मा की अनुच्छेद 535 पर निर्भरता केवल अपने तर्क के समर्थन में है, इसलिए इसके वास्तविक प्रभाव के लिए इसे नीचे दिया गया है। अनुच्छेद 535 इस प्रकार हैः

> "धारा III नकारात्मक प्रिस्क्रिप्शन
>
> अनुच्छेद 535-जिसने भी किसी अन्य के लिए कुछ करने या करने का दायित्व ग्रहण किया है, उसे दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है, यदि उसके प्रदर्शन की मांग 20 साल की अवधि के लिए नहीं की जाती है, और अनिवार्य अच्छी भावना से खड़ा होता है, पर्चे की अवधि के अंत में, या जब प्रदर्शन की मांग 30 साल की अवधि के लिए नहीं की जाती है, भले ही अच्छे विश्वास या बुरे विश्वास की परवाह किए बिना, सिवाय इसके कि विशेष पर्चे हैं। कानून में प्रदान किया गया। "

हालाँकि, इस पर भरोसा करते हुए, श्री शर्मा ने तर्क दिया कि गोवा के क्षेत्र में

लागू सीमा कानून को पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत एक स्थानीय कानून के रूप में माना जा सकता है क्योंकि यह वहां के आम आदमी के मार्गदर्शन के लिए है, क्योंकि वह अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय और व्यक्तिगत दायित्वों में अधिकारों और देनदारियों का निर्माण करता है, जिन्हें नागरिक संहिता के अनुच्छेद 535 के संदर्भ में 30 साल की अवधि के भीतर निर्वहन किया जा सकता है, विशेष रूप से, सीमा अधिनियम, 1963 की भाषा को ध्यान में रखते हुए क्योंकि स्थानीय और विशेष कानूनों को इसके तहत सुरक्षित रखा गया है, 1963 के अधिनियम में निर्धारित सीमा की अवधि लागू नहीं होगी। जस्टिनियानो के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर मजबूत निर्भरता रखी गई है और इसमें निहित तर्क श्री शर्मा द्वारा अपील के समर्थन में उनके प्रस्तुतिकरण के हिस्से के रूप में अपनाए गए हैं।

इस मामले में आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीमा विधेयक, 1963 को संसद द्वारा पारित किया गया था और बाद में 5 अक्टूबर, 1963 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 1 जनवरी, 1964 को सीमा अधिनियम 1963 (1963 का अधिनियम 36) के रूप में लागू हुआ। खंड 1 की उप-खंड 1 में प्रावधान है कि अधिनियम को सीमा अधिनियम, 1963 कहा जा सकता है और खंड 1 की उप-खंड 2 में विशेष रूप से प्रावधान है कि यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इस प्रकार संसद के इरादे को यह दर्शाने के लिए वर्गीकृत किया गया है कि इसे उन क्षेत्रों पर लागू किया जाए जो देश बनाते हैं और इस प्रकार स्पष्ट रूप से गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया है-प्रतिवादी के लिए श्री मेहता की यह प्रस्तुति काफी आकर्षक लगती है क्योंकि यह मामले की जड़ तक जाती है। लेकिन इस मोड़ पर उस पर आगे विचार किए बिना, गोवा, दमन और दीव प्रशासन, 1962 की खंड 5, जिस पर अपील के समर्थन में मजबूत निर्भरता की गई थी, सुविधा के लिए नीचे ध्यान में रखी गई है और वह नीचे दी गई हैः

"5, मौजूदा कानूनों की निरंतरता और उनका अनुकूलन। - (1) गोवा, दमन और दीव या उसके किसी भाग में नियत दिन से तुरंत पहले लागू सभी कानून किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक उसमें लागू रहेंगे।

(2) इस तरह के किसी भी कानून को लागू करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से। गोवा के प्रशासन से संबंध। दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और ऐसी किसी भी विधि के प्रावधानों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार लाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार, नियत दिन से दो साल के भीतर, आदेश द्वारा, ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है, चाहे वे निरसन या संशोधन के रूप में हों, जो आवश्यक या समीचीन हो और उसके बाद, ऐसी प्रत्येक विधि इस तरह किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगी। "

इस संदर्भ में, यह तर्क दिया गया है कि चूंकि नागरिक संहिता को निरस्त करने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसमुकदमा पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत निर्धारित सीमा जारी रहेगी और इसमुकदमा मुकदमे को सीमा के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है।

माना जा सकता है कि पुर्तगाली नागरिक संहिता अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जिसमें नागरिकों के विभिन्न अधिकारों और देनदारियों का विवरण दिया गया है और जाहिर है कि इस तरह के अधिकार के प्रवर्तन में सीमाएं नागरिक संहिता से उत्पन्न होती हैं और ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

यह सच है कि गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम, 1962 की खंड 5 के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली नागरिक संहिता जारी

रही, जिसमें प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है। हम 1962 के विनियम 12 पर भी ध्यान दें दे सकते हैं जो विनियम की अनुसूची में उल्लिखित कुछ कानूनों के विस्तार का प्रावधान करता है, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 शामिल है और इसे 1 दिसंबर, 1965 से केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव में लागू किया गया था। गोवा, दमन और दीव (कानून) संख्या 2 विनियम, 1963 (1963 का विनियम 11) में विनियम 12 में निहित प्रावधानों के समान प्रावधान पाए गए हैं, जिनके तहत भारतीय अनुबंध अधिनियम, माल की बिक्री अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश में क्रमशः 1 नवंबर, 1965 और 1 दिसंबर, 1965 से लागू किया गया था। इस प्रकार यह स्थिति (विनियम 11 और विनियम 12) से पहले यहां देखे गए दो विनियमों को ध्यान में रखते हुए सामने आती है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों को किसी अन्य क़ानून के साथ उपयुक्त विधायी प्राधिकरण द्वारा राज्य में लागू किया गया है। इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा हस्ताक्षरित वचन पत्र और इसकी गारंटी जारी करने वाले उत्तरदायी को वचन पत्र अधिनियम के अर्थ के भीतर विषय नहीं कहा जा सकता है। किसी भी स्थिति में, और स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक आधार पर, एक काल्पनिक विलेख भी मौजूद था जिसे भारतीय अनुबंध अधिनियम के अर्थ के भीतर एक अनुबंध भी नहीं कहा जा सकता है जो गोवा, दमन और दीव राज्य में लागू होता है। इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या विशिष्ट विधान जिसमें वे विषय शामिल हैं जिनके तहत वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, क्षेत्र या प्रक्रियात्मक अधिनियम को नियंत्रित करेंगे, यह मानते हुए कि शासी क़ानून के प्रतिस्थापन में इसका उचित अनुप्रयोग होगा। हालाँकि, इसमें एक व्यापक बहस शामिल है और इस पीठ को इसका जवाब देने के लिए नहीं बुलाया गया है, क्योंकि हम इसके संबंध में कोई भी राय व्यक्त करने से खुद को रोकते

हैं, लेकिन तथ्य यह है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों को ऊपर देखे गए विनियमों के संदर्भ में शामिल किया गया है और गोवा, दमन और दीव राज्य में लागू किया गया है।

यह ध्यान दिया जाए कि अनुच्छेद 535 में पुर्तगाली सिविल कोड में अनुबंधों को विनियमित करने वाले अध्याय III में सीमा के प्रावधान हैं जो -कभी, भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अनुबंध अधिनियम के तहत एक ही अध्याय में होने वाले अनुबंधों से संबंधित सीमा के लिए निर्धारित अवधि को अनुबंध के अन्य प्रावधानों के साथ जाने के बजाय एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में जीवित नहीं कहा जा सकता है, जो अनुबंध अधिनियम के अनुकूलन के कारण प्रतिस्थापित हो जाता है। अतः इसे एक निहित निरसन नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक अध्याय II का संबंध है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुकूलन के तथ्य के कारण एक स्पष्ट निरसन की आवश्यकता कभी महसूस नहीं की गई थी। या तो अध्याय अपनी संपूर्णता में जीवित रहता है या यह अपने सभी क्षेत्रों में नष्ट हो जाता है-यह अनुबंध से संबंधित एक अध्याय है और इसके प्रवर्तन की अवधि निर्धारित करता हैःकोई विच्छेदन संभव नहीं है।

गनोक्सामा बाइसी नाइक वैनगोंकर बनाम जोआओ मैनुअल डायस, 1983 (1975 की पहली दीवानी याचिका सं 27), (पणजी-गोवा में बम) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त विचार कैडर निर्माण (उपरोक्त) में खण्ड पीठ द्वारा स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय ने अंतिम उल्लेखनीय निर्णयों में पुर्तगाली संहिता के अनुच्छेद 689 और 690 पर निर्भरता रखी, जो क्रमशः त्रुटि और जबरदस्ती के मामले में सीमा की विशेष अवधि प्रदान करता है, और इस प्रकार उससे सादृश्य बनाते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गनोक्सामा के मामले (उपरोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित कानून को कानून का सही स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता है। श्री मेहता द्वारा तैयार

किया गया तर्क भी ऐसा ही है-क्योंकि अधिकार को किसी अन्य कानून द्वारा शासित होने की स्थिति में प्रवर्तन कानून के संचालन से बच नहीं सकता है।

सिविल कोड के अनुच्छेद 505 में चीजों और अधिकारों के अधिग्रहण का प्रावधान है और इसे सकारात्मक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में माना जाता है और उनकी पूर्ति की मांग नहीं करने के कारण दायित्वों के निर्वहन को नकारात्मक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। 'प्रिस्क्रिप्शन' शब्द सामान्य रूप से उस समय के दौरान निरंतर उपयोगकर्ता, अधिकार और आनंद द्वारा अंतर्निहित वंशावली के लिए शीर्षक प्राप्त करने का एक तरीका है। अनुच्छेद 535 प्रिस्क्रिप्शन के एक नकारात्मक तत्व को निर्धारित करता है जो प्रतिकूल कब्जे के समान है। तथापि, एक विहित अधिकार प्रतिकूल अधिकार से भिन्न होता है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन अवास्तविक अधिकारों से संबंधित है जबकि प्रतिकूल अधिकार संपत्ति के स्वामित्व में ब्याज पर लागू होता है। 'प्रिस्क्रिप्शन 'आमतौर पर अमूर्त वंशानुगत के अधिग्रहण पर लागू होता है और नकारात्मक प्रिस्क्रिप्शन स्पष्ट रूप से इस तरह के अधिग्रहण का निषेध है। 'प्रिस्क्रिप्शन 'बेशक, मूल कानून का एक हिस्सा है, लेकिन सीमा प्रक्रिया से संबंधित है, क्योंकि इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन सीमा से अलग है। पहला कुछ अधिकार प्राप्त करने के तरीकों में से एक है, जबकि बाद वाला अर्थात सीमा, एक उपचार को रोकता है, संक्षेप में, पर्चे एक अधिकार प्रदान किया गया है, सीमा एक उपचार के लिए एक बाधा है पुर्तगाली सिविल कोड का अध्याय प्रिस्क्रिप्शन कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम (वॉल्यूम। 72) ने 'प्रिस्क्रिप्शन' शब्द का वर्णन नीचे किया हैः

> "कानून का प्रिस्क्रिप्शन दो प्रकार का होता है; यह या तो संपत्ति के अधिग्रहण के लिए एक साधन है या केवल न्यायिक प्रक्रिया की दासता से छूट का साधन है। पहले अर्थ में, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित, प्रिस्क्रिप्शन को प्रतिकूल कब्जे में माना जाता है। दूसरे अर्थ

में, न्यायिक प्रक्रिया की दासता से छूट के संबंध में, पर्चे को कार्यों की सीमा के रूप में माना जाता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, पुर्तगाली सिविल कोड की व्याख्या से संबंधित कैडर कंस्ट्रक्शन (ऊपर) में जो व्यक्त किया गया है, उसके अलावा किसी भी विपरीत राय की अभिव्यक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

गोवा, दमन और दीव राज्य में एक अधिसूचना द्वारा वचन पत्र अधिनियम और अनुबंध अधिनियम को शामिल करने के मुकदमा के दूसरे पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुकदमे की वाद हेतुक, अर्थात समझौते के संदर्भ में उधार दिया गया धन और अग्रिम धन, वचन पत्र के स्वीकृत निष्पादन के कारण वचन पत्र अधिनियम के साथ पठित अनुबंध अधिनियम द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होता है और इस तरह से संहिता द्वारा शासित नहीं कहा जा सकता है। यदि कार्यवाही शुरू करने का अधिकार संहिता के दायरे से बाहर चला जाता है, तो बाद वाला इसकी प्रवर्तनीयता को नियंत्रित नहीं कर सकता है। सिविल कोड अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, इसकी प्रयोज्यता किसी भी तरह से प्रतिबंधात्मक नहीं थी, जो राज्य के कानून, ऊपर नामित दो कानूनों के अनुकूल अधिसूचना जारी करने से पहले थी। पुर्तगाली सिविल कोड को सीमा का अधिनियम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से मौजूदा कार्रवाई के अधिकारों के प्रवर्तन को रोकने के लिए अपने संचालन का विस्तार नहीं कर सकता है। सिविल कोड, जैसा कि ऊपर देखा गया है, को राज्य में व्यापक कानून का एक संकलन नहीं माना जा सकता है जो स्थिति को समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट अवधि के साथ स्थिति की आवश्यकता को पूरा करता है-स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि पुर्तगाली सिविल कोड अधिकार के संचय और इसकी प्रवर्तनीयता दोनों के लिए प्रदान करता है और जब अधिकार विभाजित हो जाता है, तो कोड के अलावा किसी अन्य स्रोत से उत्पन्न होने वाले अधिकार की प्रवर्तनीयता का सवाल उत्पन्न नहीं

होगा। या तो संहिता पूरी तरह से लागू होती है या नहीं-इसके बारे में कोई आधा रास्ता नहीं है। उपरोक्त के संदर्भ में, मूल और प्रक्रियात्मक मामलों के बीच अंतर से जुड़ी बहस में न तो गहराई से जाने की आवश्यकता है और न ही प्रासंगिक तथ्यों में चर्चा की जानी चाहिए, विशेष रूप से भाला बनाम हार्टली, (1800) 3 ई खंड में लॉर्ड एल्डन के कथन की आलोचना को ध्यान में रखते हुए। 81 170 ई. आर. 545 में कहा गया है कि उसके पास मौजूदा ऋण होने के कारण एक स्थायी ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं होता है, भले ही उसके उपचार को सीमा के क़ानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया था-निजी अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम में सीमा के क़ानून के वर्गीकरण के लिए प्रासंगिक तथ्यों में उपचार के आहरण और अधिकार के निर्वाह के बीच अंतर को केवल प्रक्रियात्मक कहा जाता है और इसे "कृत्रिम और ठोस" दोनों के रूप में वर्णित किया गया है (इस संदर्भ में देखें चेसिस्टियर और नॉर्थ, प्राइवेट इंटरनेशनल लिमिटेड 11 वीं संस्करण। मैकलियोड; अधिनियमों का टकराव। मैकेन बनाम आर. डब्ल्यू. मिलर एंड कंपनी के मामले में ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय। (दक्षिण ऑस्ट्रेलिया) पीटीवाई। लिमिटेड, 174 सी. एल. आर. (1991-92 पृष्ठ 1) जिसमें सी. जे. ने कहाः

> "हालाँकि, सीमा के अन्य कानून, अस्तित्व में एक अधिकार छोड़ते हुए केवल एक पक्ष को एक उपाय से वंचित करने के लिए काम नहीं करते हैं। सीमा प्रावधान जिन्हें बनाए गए अधिकारों की घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है, चाहे वे एक ही या किसी अन्य संबंधित अधिनियम द्वारा हों, आमतौर पर नामित अवधि के समाप्त होने के बाद उन अधिकारों को समाप्त करने के रूप में माना जाता है। "

इस प्रकार स्पष्ट प्रश्न यह प्रतीत होता है कि क्या इस देश के सीमा अधिनियम को गोवा राज्य पर लागू किया जाएगा, क्योंकि यह इस देश का एक भाग है या पुर्तगाली नागरिक संहिता, इस मामले के तथ्यों में जो अधिकार को नियंत्रित नहीं करते

हैं, इस तरह के अधिकार की प्रवर्तनीयता में इसका अनुप्रयोग होगा-हमारे पास इस तथ्य पर अपनी राय दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि भारतीय कानून (अर्थात, अनुबंध अधिनियम और परक्राम्य उपकरण अधिनियम) के तहत अधिकार के अस्तित्व के कारण पोर्टु-पुर्तगाली कानून के तहत उपचार के विलुप्त होने को निहित रूप से निरस्त नहीं माना जा सकता है। निहित निरसन के सिद्धांत को विचाराधीन मामले के तथ्यों में अपनी जगह लेनी होगी। अनुच्छेद 535 के तथ्य को केवल एक प्रक्रियात्मक पहलू मानते हुए और एक मूल अधिकार नहीं होने के कारण, हम निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्थिति पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूल और प्रक्रियात्मक कानून के बीच अंतर का यहां एक सार्थक अस्तित्व है। निहित अर्थहीनता के सिद्धांत, हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं, का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जहां एक विशेष प्रावधान को बनाए रखने का इरादा नहीं किया जा सकता था और यदि इसे बने रहने दिया जाता है, तो परिणामी प्रभाव एक बेतुका होगा। न्यायालय निहितार्थ द्वारा निरसन के आधार पर ऐसा घोषित किए बिना नहीं रह सकते। आइए हम इस मोड़ पर कुल प्रभाव की सराहना करने का प्रयास करें, यदि हम अनुच्छेद 535 को अस्तित्व में रहने देते हैंःगोवा राज्य को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में उत्पन्न होने वाले अनुबंध पर मुकदमा करने का अधिकार सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाता है। अपीलकर्ता बैंक की देश भर में अपनी शाखाएँ हैं, ऐसी ही स्थिति में, अपीलकर्ता बैंक अपने दावे को लागू करने का हकदार होगा, भले ही सीमा अधिनियम के तहत सीमा की अवधि निर्धारित की गई हो, लेकिन यदि ऐसा ही मुकदमा देश के किसी अन्य हिस्से में दिखाई देता है, तो अपीलकर्ता बैंक को प्रवर्तन के लिए दावा करने की स्वतंत्रता होगी और उपचार बहुत लंबे समय तक जारी रहेगा (जैसा कि इस मामले में 30 साल)। क्या यह एक कल्पना की जा सकने वाली स्थिति है कि इस देश में कोई ऋणी निजी अंतर्राष्ट्रीय

कानून के निहितार्थ के बिना एक विशिष्ट अवधि के भीतर लेनदार के दावे को ईमानदारी से और वैध रूप से समाप्त कर सकता है, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में स्थित एक ऋणी, जो ऐसे स्थानीय कानून के कारण कानूनों की एकरूपता रखता है, वह बहुत लंबी अवधि की समाप्ति तक इस तरह के उन्मूलन या उपचार के प्रतिबंध का दावा नहीं कर सकता है?- स्थिति काफी विसंगत है और इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सीमा अधिनियम की खंड 1 (2) के संबंध में, जो गोवा के क्षेत्रों के बहुत बाद लागू हुई। दमन और दीव को संविधान (बारहवें) संशोधन अधिनियम द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि, हमें लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए।

संयोग से, विधायिका को समाज की आवश्यकता और कानून की मौजूदा स्थिति के बारे में पता होना चाहिएःइस बात पर विचार करने का कोई कारण नहीं है कि विधायिका पुर्तगाली नागरिक कानूनों के संबंध में सीमा के लिए एक अलग प्रावधान के साथ मौजूदा स्थिति से अनजान थी। यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष संदर्भ दिया गया है, लेकिन भारतीय क्षेत्र के भीतर गोवा, दमन और दीव राज्य को शामिल करने के बाद, यदि स्थानीय कानून को केवल सीमा के प्रश्न से संबंधित प्रचलित करने का कोई इरादा था, तो एक स्पष्ट बहिष्कार होता और जिसकी अनुपस्थिति में में किसी भी विपरीत इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, न ही कोई विरोध निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किसी भी स्थिति में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, पुर्तगाली सिविल कोड, हमारे विचार में, भारतीय अनुबंध अधिनियम या परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली वाद हेतुक लिए सीमा की एक अलग और अलग अवधि प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि सिविल कोड को एक साधन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उससे उत्पन्न कार्रवाई के कारण को केवल उसके तहत नियंत्रित किया जाना चाहिए और अन्यथा नहीं। संपूर्ण सिविल संहिता को एक स्थानीय कानून या विशेष कानून के रूप में माना

जाना चाहिए, जिसमें उस विशेष सिविल संहिता के तहत उत्पन्न होने वाले अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीमा के प्रश्न से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, न कि उसी के बारे में और इस संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के लिए कि पुर्तगाली सिविल संहिता उस संहिता के प्रावधानों के बाहर उत्पन्न वाद हेतुक लिए सीमा की अवधि प्रदान नहीं कर सकती है, अनुमोदित है। इस मुद्दे पर एक विरोधाभासी दृष्टिकोण न केवल एक अर्थहीनतापन को जन्म देगा, बल्कि देश के कानून को पूरी तरह से अनुचित बना देगा। जहाँ तक देश के विभिन्न राज्यों में सीमा अधिनियम को लागू करने का संबंध है, वहाँ भी प्रतिकूलता होगी; जबकि गोवा, दमन और दीव में सीमा की अवधि महाराष्ट्र राज्य की तुलना में बहुत बड़ी अवधि के लिए होगी-कानून के शासन और सीमा अधिनियम के न्यायिक पहलू को ध्यान में रखते हुए स्थिति को वैचारिक रूप से भी बनाए नहीं रखा जा सकता है।

यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि सीमा के एक विशेष कानून के संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मुकदमा हमारी सहमति उस संहिता के तहत उत्पन्न अधिकारों के प्रवर्तन के मुकदमा प्रदान की गई है, इस तथ्य के कारण है कि सीमा का कानून एक प्रक्रियात्मक कानून है और मुकदमे की तारीख पर मौजूद प्रावधान उस पर लागू होते हैं (सी. बीपथुमा और अन्य बनाम वेलासरी शंकरनारायण कदम्बोलिथया और अन्य, ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 241 में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।

मान लीजिए, सीमा अधिनियम एक अधिनियम है जो अधिनियम में उल्लिखित अपवाद को छोड़कर पूरे देश में लागू सामान्य शब्दों में प्रावधानों को अधिनियमित करता है। यह वर्ष 1963 का एक बाद का क़ानून है कि पुर्तगाली नागरिक संहिता का गोवा, दमन और दीव राज्य में अनुप्रयोग था और एक पूर्ववर्ती क़ानून इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि बाद वाले को सकारात्मक भाषा में व्यक्त किया जाता है,

विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम और भारतीय अनुबंध अधिनियम के विशिष्ट अनुप्रयोग के कारणःइस प्रकार यह निहितार्थ द्वारा निरस्तीकरण नहीं कहा जा सकता है-"एक नए अधिनियम का सकारात्मक क़ानून परिचय एक नकारात्मक का संकेत देता है" (हारकोर्ट बनाम फॉक्स, (1693) 1 शो. 506.

जहां तक निहित निरसन के सिद्धांत का संबंध है, मामले के एक अन्य पहलू पर नागरिक संहिता की तुलना में ध्यान दिया जाना चाहिए। सीमा अधिनियम के तहत सीमा और तथ्य का एक मिश्रित मुद्दा होने के कारण, अदालत बचाव पक्ष द्वारा याचिका नहीं उठाए जाने के बावजूद, उसी स्वतः संज्ञान में जा सकती है, लेकिन सिविल कोड के अनुच्छेद 515 के तहत एक विशिष्ट प्रतिबंध है जो दर्ज करता है कि अदालत स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है जब तक कि पक्षकारों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया जाता है। यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का एक बार है। वैमनस्यता और विसंगति इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि संसद कानून द्वारा। बॉम्बे में उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव तक अधिकार क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1981 ने बॉम्बे में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नियत दिन से केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव तक बढ़ा दिया और न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। क़ानून [(1981 का अधिनियम) (उपर्युक्त) की खंड 9 में यह प्रावधान है कि नियत दिन से पणजी में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी और बॉम्बे में उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों की संख्या कम से कम दो होगी या जिन्हें समय-समय पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जा सकता है, इस केंद्र शासित प्रदेश में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र और शक्ति का प्रयोग आदेश के लिए पणजी में बैठेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय का अधिकार और अधिकार क्षेत्र, सीमा द्वारा वर्जित किसी कार्रवाई का संज्ञान लेने के लिए, इस प्रकार नकार दिया गया है-वैचारिक रूप से यह कल्पना करना भी एक

कठिन स्थिति है कि मामलों से निपटने के दौरान एक ही उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दो अलग-अलग क्षेत्र होंगे। पुनरावृत्ति की कीमत पर हम कहते हैं कि जबकि निहित निरसन का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन प्रासंगिक तथ्यों में, जांच के बाद, हम यह मान सकते हैं कि 1.1.1964 से अस्तित्व में आने वाले सीमा अधिनियम के तथ्य के मद्देनजर, पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुच्छेद 535 को निहित रूप से निरस्त नहीं कहा जा सकता है और इसी आधार पर जस्टिनियानो के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया जाता है। पूरे देश के लिए सीमा का एक सामान्य कानून 1963 का अधिनियम है, और पुर्तगाली नागरिक कानून को सीमा अधिनियम की खंड 29 (2) के अर्थ के भीतर सीमा की एक अलग अवधि निर्धारित करने वाले गोवा, दमन और दीव राज्य के लिए लागू एक स्थानीय कानून या विशेष कानून नहीं कहा जा सकता है और किसी भी स्थिति में, 1963 के सीमा अधिनियम के तहत स्थानीय कानून को बचाने का सवाल नहीं उठता है और न ही उठ सकता है। यह निवेदन कि अधिनियम को निरस्त करने का एक विशिष्ट उल्लेख किए बिना (1963 के बाद से सीमा अधिनियम 1908 के सीमा अधिनियम को छोड़कर किसी अन्य अधिनियम का स्पष्ट निरसन दर्ज नहीं करता है), पुर्तगाली नागरिक संहिता के निरस्त होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, निहित निरसन के सिद्धांत के कारण अच्छा नहीं हो सकता है जैसा कि ऊपर देखा गया है। उपरोक्त परिसरों में, ये अपील विफल हो जाती हैं और लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दी जाती हैं।

बीएस.

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।